



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]  
No. 136]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1987/चैत्र 9, 1909  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1987/CHAITRA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1987

आदेश

का.प्रा. 266(अ) :— 18क/आई.डी.ओ.आर.ए./87 :— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.प्रा. 320(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./79 तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) से संबंधित औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रत्यक्ष किया गया था और सचिव, एवं और उद्योग विकास विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार का, जिसे अब सचिव औद्योगिक पुनर्वर्गीकरण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय दी कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1987 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये ऐसे जारी रखने के लिये, समय-समय पर निदेश जारी किये थे । (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.प्रा. 246(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./82 तारीख 25 मई, 1982, सं. का.प्रा. 832(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./82 तारीख 24 नवम्बर, 1982, सं. का.प्रा. 385(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./83, तारीख 31 मई, 1983, सं. का.प्रा. 872(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./83 तारीख 30 नवम्बर, 1983, सं. का.प्रा. 472(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./84 तारीख 29 जून, 1984, सं. का.प्रा. 975(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./84 तारीख 29 दिसम्बर, 1984, का.प्रा. 275(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./85 तारीख 29 मार्च, 1985 एवं का.प्रा. 146(अ)/18क/आई.डी.ओ.आर.ए./86 तारीख 31 मार्च, 1986) ;

और केन्द्रीय सरकार का यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1988 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का धारा 18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-क का उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेदन देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1988 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और प्रवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा.सं. 2(23)/80-जी.पू.एस.]

ए.वी. गोकक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th March, 1987

### ORDER

S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 25th May 1982 and the Secretary, closed the Sick Industries Department, Government of West Bengal called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking;

And whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the Public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1987 (vide Orders of the Govt. of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development) Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982, S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November 1982, S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983, S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983, S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June 1984, S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984, S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985 and S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86 dated the 31st March 1986;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of the 31st March 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA, read with proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulations) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March 1988.

[File No. 2(23)|80 CUST]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.